सत्यमेव जयते

कोयला मंत्रालय

वर्ष 2022-23 के लिए कार्य योजना

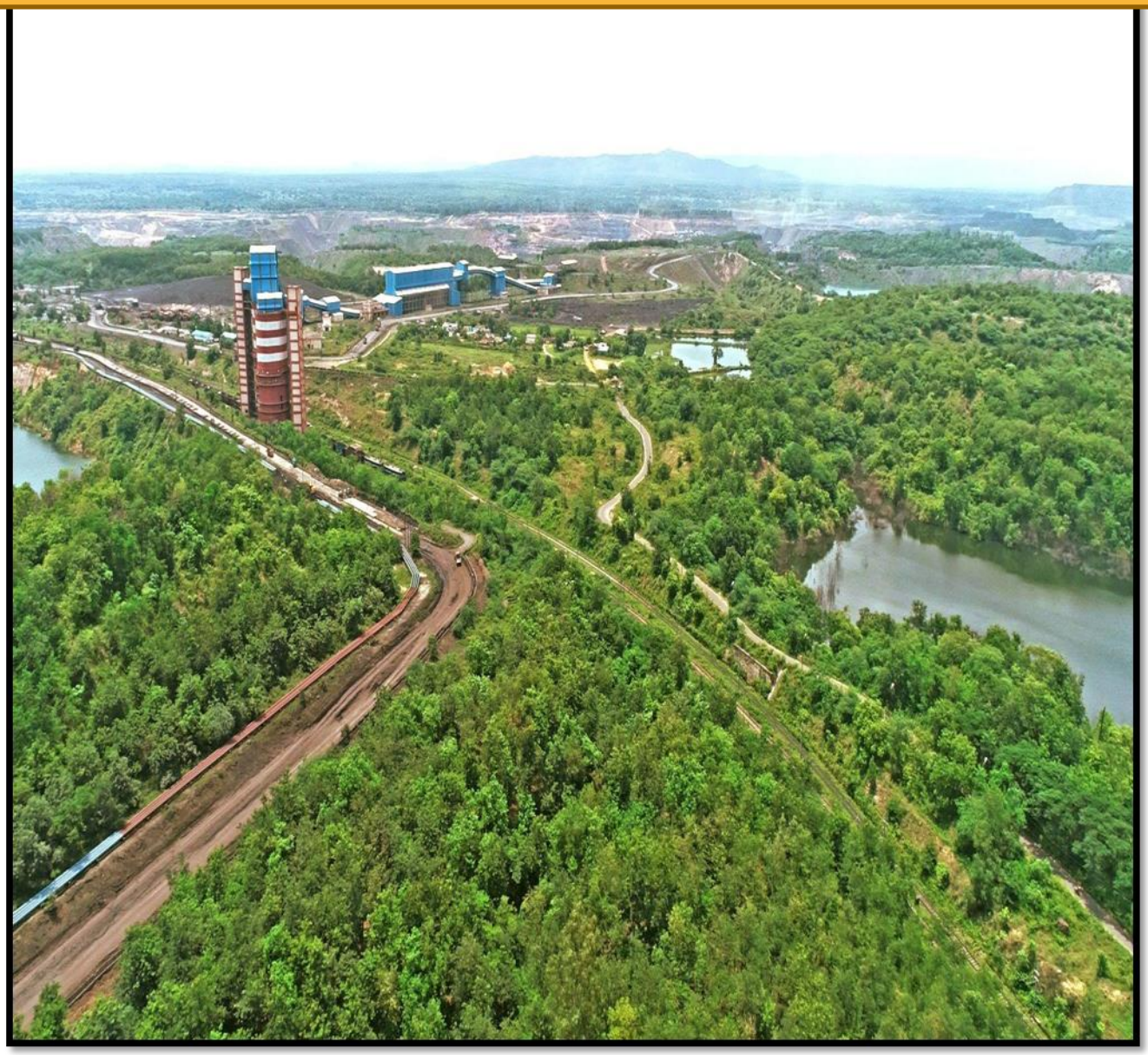

भारत की प्रगति, आत्मनिर्भर भारत के लिए, ऊर्जा आत्मनिर्भरता आवश्यक है। भारत को यह संकल्प लेना होगा कि जिस वर्ष हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएंगे, तब तक भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए।

श्री नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधान मंत्री

कोयला मंत्रालय का लक्ष्य थर्मल कोयले के आयात को न्यूनतम करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

-श्री प्रल्हाद जोशी
कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री

सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 23-24 तक घरेलू कोयला उत्पादन को 1.2 बिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।

श्री रावसाहेब पाटील दानवे
कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री

विषय - सूची

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 23 के लिए एजेंडा आइटम	संबंधित अनुभाग	संबंधित अधिकारी	पृष्ठ सं.
I	ग्रे हाइड्रोजन	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी (सीसीटी)	सलाहकार (पी)	6
II	न्यायोचित पारगमन/ऊर्जा पारगमन	सस्टेनेबिलिटी डिवीजन सेल (एसडीसी)	संयुक्त सचिव (पी एंड एस)	7-8
III	सीएमपीएफओ का पुनर्गठन	कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)	संयुक्त सचिव (स्था.)	8
IV	कोयला निकासी	कोयला परियोजना अवसंरचना मूल्यांकन और निगरानी (सीपीआईएएम)	सलाहकार (पी)	9
V	मशीनों और मात्रात्मक मापदंडों की बेंचमार्किंग (प्रति घंटा/प्रति मशीन आउटपुट)	कोयला परियोजना अवसंरचना मूल्यांकन और निगरानी (सीपीआईएएम)	सलाहकार (पी)	10
VI	सीआईएल खानों की आउटसोर्सिंग	तकनीकी प्रभाग	सलाहकार (पी)	10
VII	कोयला व्यापार प्लेटफार्म	कोयला उत्पादन और वितरण प्रभाग (सीपीडी)	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	11
VIII	कोयले के लिए नियामक तंत्र	कॉर्पोरेट मामले (सीए)	संयुक्त सचिव (स्था.)	11
IX	प्रशिक्षण	स्थापना	संयुक्त सचिव (स्था .)	11
X	कोयला क्षेत्र का कॉर्पोरेट पुनर्गठन (सीपीएसई)	कॉर्पोरेट मामले (सीए)	संयुक्त सचिव (स्था .)	12
XI	गुणवत्ता संबंधी मुद्दे	कोयला उत्पादन एवं वितरण प्रभाग (सीपीडी)	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	12-14
XII	लिग्नाइट गैसीकरण	कोयला उत्पादन एवं वितरण प्रभाग (सीपीडी)	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	14
XIII	कोकिंग कोल कार्यनीति	कोयला परियोजना अवसंरचना मूल्यांकन और निगरानी (सीपीआईएएम)	सलाहकार (पी)	15

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 23 के लिए एजेंडा आइटम	संबंधित अनुभाग	संबंधित अधिकारी	पृष्ठ सं.
XIV	कोयला मूल्य निर्धारण सुधार	कॉर्पोरेट मामले (सीए)	संयुक्त सचिव (स्था .)	16
XV	भावी एजेंडा			17-31
XV (1)	कोयला से रसायन	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी (सीसीटी)	सलाहकार (पी)	17-20
XV (2)	सीआईएल विविधीकरण	कोयला परियोजना अवसंरचना मूल्यांकन और निगरानी (सीपीआईएएम)	सलाहकार (पी)	21-24
XV (3)	ठोस मीडिया अभियान	समन्वय	संयुक्त सचिव (पी एंड एस)	25-26
XV (4)	सीएसआर गतिविधियों की कड़ी निगरानी	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कल्याण (सीएसआर एंड डब्ल्यू)		27-31
	अनुलग्नक -I	कोयले से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप		33
	अनुलग्नक-II	समेकित सीआईएल – एमडीओ परियोजनाओं की स्थिति- 30-03-22		34-37

I. ग्रे हाइड्रोजन

[कार्रवाई: सीसीटी]

कोयले से उत्पादित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए अध्ययन तथा रोडमैप तैयार करने के लिए 07.09.2021 को **अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता** में एक कार्यदल और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। कार्यदल की पहली बैठक **18.10.2021 को हुई थी।**

विशेषज्ञ समिति ने 5 बैठकें की हैं और थर्मेक्स, सीआईएमएफआर और मैसर्स दस्तूर इंजीनियरिंग द्वारा समन्वित विशेषज्ञों के समूह से प्रेजेंटेशन ली है। अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में इंडिया ग्रोथ शेल के साथ भारत में हाइड्रोजन रोडमैप और सीसीयूएस की संभावना पर मैसर्स शेल के साथ बैठक 18.02.2022 को हुई थी। समिति ने कोयले से हाइड्रोजन के लिए एक मसौदा रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिस पर अंतिम रूप देने के लिए 11.4.2022 को आयोजित समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। माननीय मंत्री द्वारा 6-5-2022 को कोयले से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप (अनुलग्नक-I) लॉन्च किया गया था।

II. न्यायोचित पारगमन/ऊर्जा पारगमन

[कार्रवाई: एसडीसी]

न्यायसंगत पारगमन के सिद्धांतों पर खान बंद करने के मामलों के निपटान पर विश्व बैंक की परियोजना

यह एजेंडा आइटम पहले से ही एजेंडा 2021-22 का हिस्सा है और एक ऑनगोइंग एजेंडा है जो वित्त वर्ष 2023 में जारी रहेगा। मौजूदा एजेंडा आइटम और भविष्य की समय-सीमा के तहत पहचान की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	गतिविधि	संभावित समय–सीमा	31.03.2022 तक की स्थिति
1.	विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) के परामर्श से प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) को अंतिम रूप देना और उसे डीईए को प्रस्तुत करना	15 जुलाई 2021	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) समय सीमा के अनुसार प्रस्तुत की गई थी। आईएमसी परामर्श के बाद, डीओई, डीईए, नीति आयोग, खान मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और एमओईएफएंडसीसी, से टिप्पणियों की प्राप्ति पर डब्ल्यूबी के परामर्श से पीपीआर संशोधित किया गया है और डीईए पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
2.	आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) का अनुमोदन	सितम्बर-21	संशोधित पीपीआर पर डीईए द्वारा मांगी गई टिप्पणियां डीओई द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। डीईए ने 25.02.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक में पीपीआर पर चर्चा की। डीईए ने पहले चरण के लिए अपनी मंजूरी के बारे में सूचित किया है यानी मैपिंग और डीपीआर तैयार करने के लिए अनुदान वित्त पोषित सहायता।
3.	सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद डब्ल्यूबी के साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू	नवंबर-21	डब्ल्यूबी ने पहले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 1.15 मिलियन अमेरीकी डालर के अनुदान से जुड़ी है।
4.	खान बंद करने से जुड़े सामाजिक पहलुओं तथा वित्त पोषण व्यवस्थाओं सहित बेस लाइन डेटा, खान बंद करने के लिए रोड मैप, खान बंद करने संबंधी गतिविधियों के विवरण को कवर करते हुए तकनीकी सहायता रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।	दिसंबर-22	डब्ल्यूबी ने पहले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 1.15 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान से जुड़ी है। डब्ल्यूबी ने सीसीएल का दौरा किया है और हितधारकों से परामर्श किया है।

क्र. सं.	गतिविधि	संभावित समय-सीमा	31.03.2022 तक की स्थिति
5.	खान बंद करने की परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर डब्ल्यूबी की दीर्घकालिक सहायता के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए डीईए को डीपीआर प्रस्तुत करना।	जनवरी-2023	
6.	2 जिलों में पायलट परियोजनाओं की शुरुआत	अप्रैल-2023	डीईए के अनुमोदन के अधीन

III. सीएमपीएफओ का पुनर्गठन

[कार्रवाई: सीएमपीएफओ]

(1). सीएमपीएफओ भर्ती नियमों की अधिसूचना:

सीएमपीएफओ के 168 वें बीओटी (बोर्ड ऑफ ट्रस्टी), द्वारा संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी । आयुक्त, सीएमपीएफओ ने भारत सरकार/कोयला मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कोयला खान भविष्य निधि (कर्मचारी) भर्ती नियम, 2017 अधिसूचित किया। कोयला मंत्रालय ने सीएमपीएफओ को दिनांक 25.04.2017 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना को डिनोटिफाई करने का निर्देश दिया। हालांकि, मंत्रालय के दिनांक 20.06.2017 के निर्देश के विरूद्ध हैदराबाद में उच्च न्यायालय में 2017 की एक रिट याचिका संख्या 22052 दायर की गई थी। मामला विचाराधीन है और सुनवाई बार-बार टल रही है।

कार्रवाई की स्थिति : - गतिरोध को तोड़ने के लिए एडिशनल एसजी (दक्षिणी क्षेत्र) से कानूनी राय मांगी गई थी। राय के आधार पर और माननीय कोयला मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, प्रस्ताव व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय को 06.12.2021 को भेजा गया है, जो कि 168 वें बीओटी द्वारा अनुमोदित संवर्ग पुनर्गठन के पूर्वव्यापी अनुमोदन के लिए है। डीओई की मंजूरी प्रतीक्षित है।

(2). सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या का युक्तिकरण:

दिनांक 31.01.2022 को सचिव (कोयला) द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में, सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया, ताकि कई स्थानों पर फैले सीएमपीएफओ कर्मचारियों को एक साथ लाकर कार्यनीतिक स्थानों पर अपने कार्यालयों को मजबूत किया जा सके। कम्प्यूटरीकरण, डेटा/रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और बेहतर ऑनलाइन संचार अवसंरचना को देखते हुए इसे व्यावहारिक और अधिक उपयोगी माना गया।

कार्रवाई की स्थिति –आयुक्त, सीएमपीएफओ को सीएमपीएफओ में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या के युक्तिकरण की जांच और खाका तैयार करना होगा। मसौदा युक्तिकरण प्रस्ताव पर पहली प्रस्तुति मई 2022के दूसरे सप्ताह तक अपेक्षित है।

IV कोयला निकासी

[कार्रवाई: सीपीआईएएम]

रेल परियोजनाएँ - कोयला निकासी के उद्देश्य से पूरे देश में 14 रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इनमें से 4 रेल परियोजनाएं डिपॉजिट आधार पर, 4 एसपीवी के माध्यम से और अन्य 6 रेलवे वित्त पोषित परियोजनाएं हैं।

एफएमसी परियोजनाएं -

सीआईएल - पहले चरण में 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजना और दूसरे चरण में 9 एफएमसी परियोजनाएं । 35 एफएमसी परियोजनाओं (प्रथम चरण) में से 6 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं और अन्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। दूसरे चरण में 9 एफएमसी परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

एससीसीएल - पहले चरण में 3 एफएमसी परियोजनाएं और दूसरे चरण में 1 एफएमसी परियोजना । एससीसीएल की एक एफएमसी परियोजना पहले ही चालू की जा चुकी है।

एनएलसीआईएल - 3 एफएमसी परियोजनाएं।

V. मशीनों और मात्रात्मक मानकों की बेंचमार्किंग (प्रति घंटा/प्रति मशीन आउटपुट)

[कार्रवाई: सीपीआईएएम]

सीआईएल, सीआईएल खानों में उपयोग किए जाने वाले एचईएमएम के वैश्विक बेंचमार्किंग मानकों और दक्षता मानकों पर अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करेगा और सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल खानों में इसके सुधार और इसकी प्रयोज्यता पर रिपोर्ट/सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। सीआईएल से एटीआर प्रतीक्षित है।

VI. सीआईएल खानों की आउटसोर्सिंग

[कार्रवाई: तकनीकी प्रभाग।]

सीआईएल एमडीओ मोड पर 15 खदानों का संचालन करेगी। 5 खदानों के लिए कार्य आवंटित किया जा चुका है। अन्य 10 खदानें निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। **(अनुलग्नक–II)**

सीआईएल ने निजी क्षेत्र को 20 बंद / परित्यक्त भूमिगत कोयला खदानों की पेशकश की है ताकि इन्हें फिर से खोला जा सके और राजस्व शेयरिंग मॉडल पर उत्पादन–रत किया जा सके। प्रस्ताव के बारे में निजी क्षेत्र को जानकारी देने के लिए 06.05.2022 को मुंबई में एक निवेशक बैठक का आयोजन किया गया।

VII. कोयला व्यापार प्लेटफॉर्म

[कार्रवाई: सीपीडी]

क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) को कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय की सहायता के लिए कार्यनीतिक और कार्यान्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देश में कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोयला बाजार खुल जाएगा और बाजार में आसानी से कोयला उपलब्ध होगा।

VIII. कोयले के लिए नियामक तंत्र

[कार्रवाई: सीए]

कोयला मंत्रालय पहले से मौजूद गैर-सांविधिक कोयला नियामक को सक्रिय करने और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्थान बनाने के लिए मौजूदा कोयला नियामक के साथ सीसीओ का विलय करने पर विचार कर रहा है, जो तकनीकी विशेषज्ञता के अलावा निजी क्षेत्र पर नजर रख सकता है। प्रस्ताव सचिव (कोयला) और माननीय कोयला मंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

IX. प्रशिक्षण

[कार्रवाई: स्थापना]

सीआईएल की प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण/प्रशिक्षण नीति की प्रगति की समीक्षा के लिए पिछली बैठक अपर सचिव (वीकेटी) की अध्यक्षता में 11.02.2022 को आयोजित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि सीआईएल अपनी उभरती भूमिका के अनुरूप सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण सामग्री का मूल्यांकन जारी रखेगा, और इष्टतम उपयोग की योजना बनाएगा। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) को कार्यकारी मैनपावर के साथ शुरू किया जाएगा और धीरे-धीरे गैर-कार्यकारी मैनपावर के लिए शामिल किया जाएगा। सीआईएल संविदात्मक कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत मूल्यांकन करेगी। सीआईएल ने बताया कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में रखे जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सीआईएल जुलाई 2022 तक प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण पर एटीआर प्रस्तुत करेगा।

सीआईएल के कार्यकारी मैनपावर के लिए टीएनए अप्रैल, 2022 के दूसरे सप्ताह तक शुरू किया जाएगा। सीआईएल ने आगे बताया कि टीएनए कार्यवाही मई, 2022 से शुरू होकर 9 महीनों में पूरी हो जाएगी और सीआईएल मैनपावर के लिए प्रक्रिया पूरी होने के बाद संविदा कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। हालांकि, सचिव (कोयला) ने सीआईएल को टीएनए के लिए समय कम करने और इसे 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। निदेशक (कार्मिक), सीआईएल से 07.04.2022 को टीएनए के लिए समय सीमा कम करने और इस मंत्रालय को एटीआर जमा करने का अनुरोध किया गया है। इसकी सूचना निदेशक (कार्मिक), सीआईएल को टेलीफोन पर भी दी गई थी। सीआईएल से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

X. कोयला क्षेत्र का कॉर्पोरेट पुनर्गठन (सीपीएसई)

[कार्रवाई: सीए]

सीआईएल के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में ,सीएमपीडीआईएल और बीसीसीएल को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। सीएमपीडीआईएल और बीसीसीएल के %25 शेयरों की प्रारंभिक सूची के लिए मसौदा कैबिनेट नोट को माननीय कोयला मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। सीआईएल बोर्ड ने 25 फीसदी शेयरों की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद ,सीएमपीडीआईएल के संबंध में कैबिनेट नोट कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया है। बीसीसीएल के संबंध में मसौदा कैबिनेट नोट आईएमसी परामर्श के लिए भेजा गया है।

XI. गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

[कार्रवाई: सीपीडी]

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत यूटिलिटिज) की चिंताओं को दूर करने के लिए, लोडिंग एंड पर 2015 में थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) आरंभ की गई है ताकि कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, जिसके लिए केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर, एक सीएसआईआर संस्थान) को कोयला कंपनियों और विद्युत क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से लगाया गया है। लोडिंग एंड पर कोयले के नमूने और परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियों), क्रेता (विद्युत यूटिलिटीज) और सीआईएमएफआर के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। लिंकेज नीलामी के माध्यम से कोयला लेने वाले गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नमूना सुविधा का विस्तार करने और विद्युत के लिए विशेष फॉरवर्ड नीलामी के तहत विद्युत यूटिलिटीज को आपूर्ति करने के लिए, क्यूसीआई और आईआईटी-आईएसएम को लगाया गया है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार थर्ड पार्टी सैंपलिंग कार्य करने के लिए क्रमशः सीआईएमएफआर, क्यूसीआई, कोटेकना और एसजीएस के साथ 595 मि.ट., 209 मि.ट., 1 मि.ट. और 5 मि.ट. की मात्रा पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगरेनी कोलयरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा सीआईएमएफआर और एलएलसीटी को वर्ष 2021-22 के लिए नमूना कार्य करने के लिए क्रमशः विद्युत क्षेत्र के लिए 50.73 मि.ट. और गैर-विद्युत क्षेत्र के लिए 0.28 मि.ट. मात्रा आवंटित की गई थी।

सुधार प्रक्रिया के रूप में ,यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए टीपीएस (थर्ड पार्टी सैंपलिंग) एजेंसियों को पीएफसी द्वारा सूची में शामिल किया जाएगा। पीएफसी ने अब सीआईएमएफआर के अलावा एजेंसियों को पैनल में शामिल कर लिया है और उपभोक्ता, पैनल में शामिल किसी भी एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। मित्रा एसके प्राइवेट लिमिटेड को पीएफसी द्वारा 28.12.2021 को सूची में शामिल किया गया है।

कोल इंडिया ने निम्नलिखित सूचित किया है:

- <u>गुणवत्ता के मुद्दे 2021-22 (अद्यतित)</u>

    - सभी साइलो/सीएचपी पर ऑटो मैकेनिकल सैम्पलर्स (एएमएस) की निगरानी ताकि अधिक से अधिक एएमएस संचालन में रहे और कोई मैनुअल हस्तक्षेप न हो।
    - एमसीएल ,एसईसीएल और एनसीएल में बारह एएमएस कार्यरत हैं।
    - बिना किसी व्यावसायिक निहितार्थ के उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ई-नीलामी से पहले पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा परीक्षण के लिए एसओपी।
      -ई-नीलामी के लिए बोली लगाने से पहले ई-नीलामी खरीदारों को कोयला भंडार से नमूनों का परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए एसओपी तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    - रेफरी पेंडेंसी को कम करने और खातों के तेजी से निपटान के लिए अधिक रेफरी लैब (एनएबीएल) को पैनल में रखा जाएगा।
    - इस मुद्दे पर 13वीं शीर्ष समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और अंतिम एमओएम की प्रतीक्षा है।
    - मार्च 2022 के भीतर एमसीएल और एनसीएल में सफल परीक्षण के बाद ऑनलाइन विश्लेषक के कोयला गुणवत्ता परिणामों (नमी, राख और जीसीवी) के डेटा विश्लेषण के आधार पर भविष्य की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा, जो कि भेजे गए कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक फीडबैक सिस्टम के रूप में है।
      अप्रैल 2022 के दूसरे सप्ताह तक ऑनलाइन विश्लेषक चालू होने की उम्मीद है ।

2022-23 के लिए गुणवत्ता संबंधी उपलब्धियां

- जहां संभव हो, सभी साईलो/सीएचपी पर ऑटो मैकेनिकल सैम्पलर्स (एएमएस) की स्थापना और केलीब्रेशन, ताकि अधिक एएमएस परिचालन में रहे और सैंपलिंग प्रक्रिया में कोई मैन्युअल हस्तक्षेप न हो।
- एफएसए प्रावधानों के अनुसार केवल साइज्ड कोयले की आपूर्ति।
- 58 प्रयोगशालाओं में से शेष 2 प्रयोगशालाओं नामतः एसपी माइंस (ईसीएल) और बैकुंठपुर (एसईसीएल) की एनएबीएल मान्यता।
- बीसीसीएल और सीसीएल में प्रत्येक में केवल 2एनएबीएल प्रयोगशालाएं हैं। बीसीसीएल और सीसीएल के विभिन्न प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 6 करने का प्रस्ताव है।
- रेफरी पेंडेंसी को कम करने और खातों के तेजी से निपटान के लिए अधिक रेफरी लैब (एनएबीएल) को पैनल में रखा जाएगा।
- सहायक कंपनियों द्वारा कोकिंग कोल खानों के सीमों के संबंध में कोकिंग कोल मापदंडों को अपलोड करना– पीएमडी, सीआईएल द्वारा सीएमपीडीआईएल को कोकिंग कोल गुणवत्ता मानकों के परीक्षण मानों को सामने लाने का काम सौंपा गया है।

XII. लिग्नाइट गैसीकरण

[कार्रवाई: सीसीटी]

विविधिकरण पहलों के हिस्से के रूप में नेवेली, तमिलनाडु में 0.4 एमटीएलए क्षमता का लिग्नाइट आधारित सतही गैसीकरण और मेथनॉल संयंत्र (मेथनॉल-I) स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना की प्रगति निम्नानुसार है:

- मैसर्स पीडीआईएल के माध्यम से विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार कर ली गई है।
- परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन एसबीआई कैप्स के माध्यम से पूरा किया गया है।
- परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) पूरी हो गई है और पीडीआईएल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
- संयंत्र स्थल पर प्रारंभिक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और नींव के डिजाइन के लिए भू-तकनीकी जांच पूरी हो गई है।
- मैसर्स पीडीआईएल को ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने और परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त एजेंसी की पहचान करने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- डीएफआर को मंजूरी और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

पिछले वर्ष 2021-22 के एजेंडा से निम्नलिखित एजेंडा बिंदु:

XIII कोकिंग कोल कार्यनीति

[कार्रवाई: सीपीआईएएम]

मंत्रालय द्वारा कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है ताकि कोकिंग कोल के उत्पादन को 2020-21 में 45.00 मि.ट. से बढ़ाकर 2029-30 तक 140 मि.ट. किया जा सके जिसमें सीआईएल से 105 मि.ट. शामिल है।

कोकिंग कोल वॉशरीज की स्थापना :

सरकार की योजना इस्पात क्षेत्र को धुले हुए कोकिंग कोल की आपूर्ति 2020-21 में 4.42 मि.ट. से बढ़ाकर 2029-30 तक 25.33 मि.ट. करने की है। इसमें सेल और टाटा स्टील से प्रस्तावित 8.00 मि.ट. धुले हुए कोयले का उत्पादन शामिल है। इसे प्राप्त करने के लिए नई कोकिंग कोल वॉशरीज की परिकल्पना की गई है। विवरण इस प्रकार है:

पहले चरण में कुल 8 कोकिंग कोल वॉशरियों में से :

- 2 कोकिंग कोल वाशरीज का निर्माण और संचालन।
- 3 निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 1 का उद्घाटन हो चुका है।
- वाशरीज के लिए एलओआई / डब्ल्यूओ जारी किया गया
- एक में निविदा मंगाई गई और जिसे खोला जाना है

दूसरे चरण में 4 और कोकिंग कोल वॉशरियां:

- 01 कोकिंग कोल वाशरी का निविदा शीघ्र होना है
- 03 कोकिंग कोल वाशरीज की परिकल्पना की गई, स्थलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

XIV. कोयला मूल्य निर्धारण सुधार

[कार्रवाई: सीए]

14.01.2022 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में कोयला मूल्य निर्धारण सुधारों के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की गई। सीआईएल को 50-100 जीसीवी के टोलरेंस प्रोविजन के साथ कोयला ग्रेड के पुनर्गठन के अन्वेषण और अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। 25.02.2022 को एक अनुवर्ती समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां सीआईएल ने यह कहते हुए अपना अध्ययन प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त प्रावधान उनके लिए वित्तीय रूप से लाभकारी नहीं है। सीआईएल को वर्षों की संख्या, जिसके लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है, बढ़ाते हुए पुन: अध्ययन करने के लिए कहा गया है। सीआईएल ने आधार वर्ष को बढ़ाकर दो साल यानी 2019-20 और 2020-21 कर अपना प्रेजेंटेशन जमा कर दिया है। इस विश्लेषण में भी सीआईएल ग्रेड स्लिपेज में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं होने के साथ टोलरेंस प्रोविजन को चुनकर राजस्व हानि उठा रहा है।

XV. भावी एजेंडा

XV (1) कोयला से रासायनिक

[कार्रवाई: सीसीटी]

कोल बेड मीथेन:

झरिया सीबीएम ब्लॉक- I के लिए कोल बेड मीथेन डेवलपर (सीबीएमडी) को नियुक्त किया गया है। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक- I के लिए वैश्विक निविदाएं क्रमशः 3 और 2 बार प्रकाशित की गईं, हालांकि इन दोनों सीबीएम ब्लॉकों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

इन तीन सीबीएम ब्लॉकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	अवरोध पैदा करना	सहायक कंपनी	क्षेत्र (किमी 2)	सीबीएम संसाधन (बीसीएम)
1	झरिया सीबीएम ब्लॉक-I	बीसीसीएल	~26.55	25 बीसीएम
2	रानीगंज सीबीएम ब्लॉक	ईसीएल	~33	2.2 बीसीएम
3	सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक	एसईसीएल	~51	0.5 बीसीएम

सतही कोयला गैसीकरण:

पायलट आधार पर दो गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पहला, पेट कोक के साथ उच्च राख वाले कोयले साथ मिश्रित और दूसरा, प्रौद्योगिकी स्थापित करने के उद्देश्य से कम राख कोयले से मिश्रित इन 2 परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- **तालचर उर्वरक संयंत्र** : पेट कोक के साथ मिश्रित उच्च राख कोयले पर आधारित कोयला गैसीकरण। निवेशः 13277 करोड़ रुपये। सीआईएल, आरसीएफ और गेल इक्विटी पार्टनर (28%) हैं और परियोजना को बैंकों से ऋण (72%) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। कोयला स्रोत **: ओडिशा में** अर्कपाल ब्लॉक के उत्तर से 2.5 मि.ट. टीएफएल को कोयला उपलब्ध कराने के लिए आंवटित और पेट कोक तालचर रिफाइनरी से प्राप्त किया जाएगा।

- **दानकुनी मेथनॉल संयंत्र:** कम राख वाले कोयले पर आधारित कोयला गैसीकरण। निवेश: 5800 करोड़ रुपये । बीओओ मोड के माध्यम से प्रोजेक्ट योजना बनाई गई और संभावित निवेशकों द्वारा निवेश किया जाएगा। कोयला स्रोत : 1.5 मि.ट. कोयले की आपूर्ति ईसीएल की सोनपुरबाजारी खानों से की जाएगी।

अद्यतन स्थिति - इस संयंत्र की स्थापना के लिए बिल्ड-ओन-ऑपरेटर (बीओओ) प्रोसेसर के चयन और 25 वर्षों के लिए इसके संचालन के लिए निविदा दस्तावेज मैसर्स पीडीआईएल द्वारा तैयार किया गया है और 25 सितंबर, 2020 को मैसर्स पीडीआईएल द्वारा निविदा मंगाई गई है। बोली 16.04.2021 को खोली गई है और एक बोलीदाता (मैसर्स प्रोडेयर एयर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पीडीआईएल बोलीदाता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का मूल्यांकन कर रहा है। यह निविदा निरस्त की जा रही है।

परियोजनाएं: कोयला गैसीकरण की दिशा में प्रयासों को बढ़ाना।

दानकुनी परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन और वित्तीय व्यवहार्यता की स्थापना के आधार पर, कम राख वाले कोयले से गैसीकरण को बढ़ाने के लिए चरण II में 4 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

एस.एन.	नाम	राज्य	कोयला फीड	गुणवत्ता
1	शिल्पांचल	पश्चिम बंगाल	1.35 मि.ट.पीए	कम राख
2	उत्कर्ष	महाराष्ट्र	0.79 मि.ट.पीए	कम राख
3	महामाया	छत्तीसगढ	1.35 मि.ट.पीए	कम राख
4	अशोक	झारखंड	पीएफआर की तैयारी	उच्च राख

- वित्त वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल मे दानकुनी में बीओओ आधार पर लगभग एक बिलियन अमेरीकी डॉलर की लागत से कोयला से मेथनाल में परिवर्तन हेतु सीआईएल की पहली परियोजना शुरू की गई थी । यूएस के वायु उत्पादों से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यह निविदा निरस्त की जा रही है। दो और निविदाएं, एक छत्तीसगढ़ में एसईसीएल द्वारा और दूसरी पश्चिम बंगाल में ईसीएल द्वारा क्रमशः अमोनिया और मेथनॉल के लिए फरवरी, 2022 में जारी की जा चुकी हैं। डब्ल्यूसीएल में अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए परियोजना के लिए निविदा मई, 2022 तक जारी होने की संभावना है। सीसीएल परियोजना के लिए पीएफआर तैयार की जा रही है और सीआईएल तथा भेल संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।

कोयले से रसायनों पर सीआईएल से इनपुट:

क. दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स (DCC):

सीआईएल बिल्ड-ओन-ऑपरेटर (बीओओ) मोड के माध्यम से कोलकाता के पास डीसीसी में 0.676 मि.ट.पीए क्षमता (मेथनॉल) के एससीजी आधारित कोल-टू-मेथनॉल संयंत्र की स्थापना की संभावनाएं तलाश रहा है। इस परियोजना में रानीगंज कोलफील्ड्स से लगभग 1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष कम राख (25% तक) वाले कोयले का उपयोग किया जाएगा। इस संयंत्र की स्थापना के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन और 25 वर्षों के लिए इसके संचालन के लिए निविदा दस्तावेज मेसर्स पीडीआईएल द्वारा तैयार किया गया है और निविदा 25 सितंबर 2020 को मेसर्स पीडीआईएल द्वारा जारी की गई है। बोली 16.04.2021 को खोली गई है। एक बोलीदाता (मैसर्स प्रोडेयर एयर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

स्थिति:

पीडीआईएल ने 'नॉन–रिस्पांसिव' के रूप में प्राप्त बोली का मूल्यांकन करने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया रद्द करने की सिफारिश की है। नीति आयोग द्वारा 15.12.2021 की बैठक मे लिए गए निर्णय से भिन्न सीआईएल ने बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत के प्रत्युत्तर पर स्वतंत्र विधिक निर्णय लिया है। प्रदान की गई कानूनी राय पीडीआईएल की सिफारिश के अनुरूप है। स्वतंत्र कानूनी राय के आधार पर सीआईएल की आंतरिक मॉडरेशन समिति ने निविदा रद्द करने के लिए पीडीआईएल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सीआईएल ने निविदा पर अंतिम निर्णय के लिए सीआईएल बोर्ड में प्लेसमेंट से पहले उनके इनपुट / सलाह के लिए इसे एमओसी 28-12-2021 को अग्रेषित कर दिया है । प्रस्तुत बोली की वैधता

प्रारंभ में 12.01.2021 तक थी जिसे 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह निविदा रद्द की जा रही है।

ख. सहायक कंपनियों की सतही कोयला गैसीकरण परियोजनाएं:

1. ईसीएल- सोनपुर बाजारी क्षेत्र में शिल्पांचल एससीजी परियोजना , अंतिम उत्पाद: मेथनॉल

स्थिति: मेसर्स पीडीआईएल द्वारा 31 जनवरी , 2022 को बहादुरपुर , रानीगंज कोलफील्ड, पश्चिम बंगाल में भूतल कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल परियोजना की स्थापना और 25 वर्षों के लिए इसके संचालन के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा जारी की गई है। अनुसूचित बोली जमा करने की अंतिम तिथि 04.05.2022 है ।

2. सीसीएल- अशोक क्षेत्र में अशोक एससीजी परियोजना , अंतिम उत्पाद: अमोनियम नाइट्रेट

स्थिति: अमोनियम नाइट्रेट के लिए पीएफआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है

3. एसईसीएल- भटगांव क्षेत्र में महामाया एससीजी परियोजना, अंतिम उत्पाद: अमोनिया

स्थिति: मेसर्स पीडीआईएल द्वारा 29 जनवरी , 2022 को महामाया एससीजी प्लांट, भटगांव क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में भूतल कोयला गैसीकरण आधारित अमोनिया संयंत्र की स्थापना और 25 वर्षों के लिए इसके संचालन के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा जारी की गई है। अनुसूचित बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28.04.2022 है।

4. डब्ल्यूसीएल- जूनाकुनाड क्षेत्र में उत्कर्ष एससीजी परियोजना , अंतिम उत्पाद: अमोनियम नाइट्रेट

स्थिति: मेसर्स ईआईएल द्वारा बीओओ निविदा दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और निविदा मई 2022 के अंतिम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।

XV(2). सीआईएल विविधीकरण

[कार्रवाई: सीपीआईएएम]

विविधीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के आख्यान के आलोक में, गैर-कोयला में विविधता लाने, नए व्यवसायों को सुरक्षित करने, अपनी बैलेंस शीट में बड़े पैमाने पर भंडार / धन का उपयोग करने, कोयला-खान श्रमिकों के दीर्घकालिक भविष्य के प्रति भरोसेमंद जिम्मेदारी, आर्थिक विकास में तेजी, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में, प्रतिस्थापन योग्य कोयला आयात को समाप्त करने और 2029-30 तक 100 मि.ट. कोयला गैसीकरण और संभावित कोयला निर्यात का समर्थन करने के लिए कोयला खदानों और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है।

विविधीकरण के चार व्यापक बास्केट निम्नानुसार परिकल्पित किए गए हैं:

i. सीआईएल/एनएलसीआईएल को कोयला कंपनियों से ऊर्जा कंपनियों में बदलने के लिए नए व्यावसायिक क्षेत्र (विविधीकरण)
ii. कोयला व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी से संबंधित)
iii. कोयला खनन परियोजनाएं (मुख्य व्यवसाय) 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने में मदद करेंगी और संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करेंगी।
iv. पहली खान संपर्क परियोजना

उपरोक्त परियोजनाओं की इस मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

सीआईएल के इनपुट्स

1. एल्यूमिनियम परियोजना:

- प्रारंभ में, नाल्को के साथ संयुक्त उद्यम में एल्युमीनियम परियोजना (एल्यूमीनियम स्मेल्टर और कैप्टिव विद्युत प्लांट) शुरू करने की परिकल्पना की गई थी और परियोजना के लिए प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल यह था कि एमसीएल के पास 74% इक्विटी होगी और नाल्को के पास संयुक्त उद्यम में 26% इक्विटी होगी। इसके अलावा, प्रस्तावित परियोजना के लिए एल्यूमिना की आपूर्ति नाल्को द्वारा की जानी थी और कोयले की आपूर्ति एमसीएल द्वारा की जानी थी।

- तथापि, 6 अगस्त, 2021 को सीआईएल की विविधीकरण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक और तत्पश्चात् 17 अगस्त, 2021 की समीक्षा बैठक के दौरान, एमसीएल-नाल्को एल्युमिनियम परियोजना को विविधीकरण एजेंडे से हटाने का निर्देश दिया गया था।

- एमसीएल-नाल्को परियोजना को विविधीकरण योजना से हटा दिए जाने के मद्देनजर, बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना रिफाइनरी, एल्यूमीनियम गलाने और संबद्ध सीपीपी सहित एकीकृत ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि एमसीएल-नाल्को परियोजना के स्मेल्टर और सीपीपी के लिए प्रस्तावित स्थान का उपयोग इस एकीकृत ग्रीनफील्ड एल्युमीनियम परियोजना के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रस्तावित परियोजना के लिए ओडिशा में एक उपयुक्त बॉक्साइट ब्लॉक की पहचान और अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। एल्युमीनियम गलाने के लिए बॉक्साइट खनन की पूर्ण एकीकृत परियोजना के लिए ब्लॉक बॉक्साइट ब्लॉक के स्थान पर एक एल्यूमिना रिफाइनरी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

- मैसर्स डेलॉइट टौच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी ने संशोधित पीएफआर प्रस्तुत किया है जिसे 238 वें एमसीएल बोर्ड द्वारा 24.09.2021 को अनुमोदित किया गया है और सीआईएल के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की गई है। तदनुसार, सीआईएल के 432वें बोर्ड ने संशोधित डीपीआर को मंजूरी दे दी है। सीआईएल ने आईपीआईसीओएल के गो-स्विफ्ट पोर्टल में सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया है। ओडिशा में एकीकृत एल्युमीनियम परियोजना के लिए इक्विटी साझेदारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए 30.11.2021 को एक आरएफक्यू जारी किया गया है।

- ओडिशा राज्य में एकीकृत ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम परियोजना के प्रस्ताव को 21 दिसंबर, 2021 को ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- सीआईएल ने रायगडा जिले (एल्यूमिना रिफाइनरी की प्रस्तावित साइट) और नेउलापोई (स्मेल्टर और सीपीपी की प्रस्तावित साइट) में साइट का दौरा किया है।

- प्रस्तावित परियोजना के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17ए (2) के तहत ओडिशा राज्य में उपयुक्त बॉक्साइट ब्लॉक (सिजिमाली / कुट्रमाली) के आवंटन के लिए आवेदन किया गया है । बॉक्साइट ब्लॉक के लिए फिलहाल मंजूरी का इंतजार है।

- सीआईएल ने प्रस्तावित परियोजना के लिए इक्विटी पार्टनर योग्यता के लिए एक ईओआई जारी किया है और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई गई है, वर्तमान में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल, 2022 है।

2. सौर पीवी विनिर्माण

- सीआईएल ने अपने विविधीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सौर पीवी विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इसलिए, परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए, सीआईएल भारत सरकार द्वारा घोषित पीएलआई प्रोत्साहन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है । इस प्रकार, योजना के अनुरूप, सीआईएल ने 4जीडब्ल्यू वेफर टू मॉड्यूल के लिए पीएलआई निविदा में भाग लिया है। पीएलआई निविदा के लिए तकनीकी बोलियां 21.09.2021 को खोली गई थीं। लगभग 54.8 गीगावॉट की सामूहिक क्षमता के लिए 18 बोलियां प्रस्तुत की गई हैं। वित्त खोला गया है और पीएलआई परिणाम में सीआईएल को प्रतीक्षा सूची (क्रमांक 5 पर) में रखा गया है

- सीआईएल संयंत्र के लिए सबसे व्यवहार्य और संभावित स्थान का भी मूल्यांकन कर रहा है। कडप्पा (एपी), धोलेरा (गुजरात) और कुड्डालोर (तमिलनाडु) नाम के तीन स्थानों को पीएलआई निविदा में अस्थायी स्थानों के रूप में उद्धृत किया गया है। एपी और गुजरात की सरकारों से बनी-बनाई प्रोत्साहन पेशकश पर औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। कुड्डालोर , गंगईकोंडन और ओडिशा (थिरुनेलवेली जिला) साइट का दौरा किया गया है।

- इक्विटी पार्टनर के चयन के लिए आरएफक्यू किया गया है। बीएचईएल और रीन्यू सोलर (शक्ति फोर) प्राइवेट लिमिटेड को अगले चरण के आरएफपी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

3. थर्मल उत्पादन :

- सीआईएल अपनी विविधीकरण योजना के अनुरूप कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन व्यवसाय में विविधीकरण की योजना बना रहा है। इसलिए, योजना के अनुसार, सीआईएल ने अपनी सहायक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के माध्यम से एटीपीएस 1X660 मेगावाट संयंत्र स्थापित करने के लिए एमपीपीजीसीएल के साथ साझेदारी करने की योजना बनाई है। पास के कोरबा क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति की जाएगी, ताकि प्लांट लगभग पिट-हेड प्लांट के समान ही स्थापित किया जा सके।
- मसौदा समझौता ज्ञापन सीआईएल के कानूनी सलाहकार द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है और बाद में एमपीपीजीसीएल द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। इक्विटी निवेश और एमओयू के मसौदे पर एसईसीएल और सीआईएल बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
- एमओसी ने पत्र दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से परियोजना के सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है।
- अगले चरण के रूप में, एसईसीएल और एमपीपीजीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा।

4. सौर

- सीआईएल ने 2023-24 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए 3000 मेगावॉट पीक का लक्ष्य रखा है। सीआईएल ने अब तक 22 जनवरी तक 8.436 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इसके अलावा, 455 मेगावाट (एसईसीएल-140 मेगावाट, एमसीएल- 50 मेगावाट, एनसीएल-50 मेगावाट, सीआईएल-100 मेगावाट, बीसीसीएल-45 मेगावाट, सीसीएल) की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाएं -20 मेगावाट, ईसीएल-35 मेगावाट, डब्ल्यूसीएल-15 मेगावाट) क्षमता पाइपलाइन में है। सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स स्थापित करके नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनने का रोडमैप नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
एमडब्ल्यूपी में क्षमता	291 मेगावाट, 8.436 मेगावाट (फरवरी 2022 तक पूर्ण)	1500	1213	3000

- 190 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स (गुजरात-100 मेगावाट में जीयूवीएनएल, एमसीएल-50 मेगावाट, एसईसीएल -40 मेगावाट) के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं और कमीशनिंग के विभिन्न चरणों में हैं। एनसीएल में 50 मेगावाट की परियोजना के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और एक सप्ताह के भीतर कार्य आदेश दिए जाने की संभावना है। सीआईएल/सहायक कंपनियों में 11 मेगावाट की रूफटॉप परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
- सीआईएल निवल-शून्य ऊर्जा कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अखिल भारतीय निविदाओं में भाग ले रही है।
- सीआईएल ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-पारंपरिक) व्यवसाय में उद्यम करने के लिए 'सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड' नामक एक सहायक कंपनी को शामिल किया है।

XV(3). ठोस मीडिया अभियान

[कार्रवाई: समन्वय]

एनएलसीआईएल ,एससीसीएल ,सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के साथ सात बैठकें की गईं।

मसौदा मीडिया अभियान चालू है तथापि विजुअल मीडिया सहित लघु फिल्मों जैसे मीडिया कार्यनीति को कवर करते हुए कुछ अन्य बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है।

एक नया आईटी और मीडिया सेल एससीसीएल, एनएलसीआईएल, सीआईएल और सहायक कंपनियों से मीडिया की प्रतिक्रिया को प्रभावित करेगा।
सीपीएसयू मीडिया योजना के लिए ब्रीफ:

- इस संबंध में पहली बैठक संयुक्त सचिव (समन्वय) द्वारा 17.05.2021 को वीसी के माध्यम से कोयला क्षेत्र के लिए धारणा प्रबंधन के लिए आवश्यक मजबूत मीडिया अभियान पर की गई थी।
- दूसरी बैठक संयुक्त सचिव (समन्वय) द्वारा दिनांक 10.06.2021 को कोयला क्षेत्र के लिए मीडिया अभियान पर कोयला कंपनियों के साथ की गई थी।

- सीआईएल मीडिया योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में इसी तरह की तीसरी बैठक श्री आरआर मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार एसडीसी द्वारा 10.08.2021 को ली गई थी।
- सीआईएल मीडिया टीम द्वारा सीआईएल मीडिया योजना 13.08.2021 को सचिव (कोयला) को प्रस्तुत की गई थी।

- सीआईएल ने 13.08.2021 को बैठक के लिए अंतिम प्रस्तुतिकरण साझा किया है। उसी के लिए संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं-

  - सीआईएल मीडिया प्लान के केंद्र बिंदु
  - सामान्य गतिविधियों और सीआईएल विशिष्ट गतिविधियों की सूची
  - सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए संबंधित मीडिया योजना
  - सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सोशल मीडिया उपस्थिति पर डेटा

ईटी नाउ स्वदेश पर कोल इंडिया की कहानी
https://www.youtube.com/watch?v=1zg23PyoBtc

- अंतिम मीडिया योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पांचवीं बैठक संयुक्त सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में 17.11.2021 को की गई।
- छठी बैठक 06.01.2022 को आयोजित की गई थी।
- सातवीं बैठक 12.05.2022 को आयोजित की गई थी।

सीआईएल के इनपुट्स

एक मजबूत मीडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में सीआईएल की सभी नई पहलों और प्रयासों को प्रिंट, एवी मीडिया को भेजा जाता है और कंपनी के सभी सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

मजबूत मीडिया अभियान के परिणाम का एक व्यापक प्रशंसापत्र मीडिया कवरेज में परिलक्षित होता है जिसमें टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया पर अध्यक्ष सीआईएल के साक्षात्कार, ई-बुक प्रकाशन, ईसीएल की मीडिया यात्रा के आधार पर तैयार समाचार, विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित समाचार, फिल्में और मोशन ग्राफिक्स साझा करने योग्य गूगल ड्राइव लिंक में सबमिट किए जा रहे हैं

XV(4). सीएसआर कार्यकलापों की कड़ी निगरानी

कार्रवाई- सीएसआर एंड डब्ल्यू

सीआईएल में सीएसआर कार्यकलाप:

सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सीआईएल की सहायक कंपनियों को तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% या किसी विशेष वर्ष में सीएसआर गतिविधियों के लिए उस सहायक कंपनी के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के कोयला उत्पादन का 2 प्रति टन, जो भी अधिक हो आवंटित करना होता है। सीआईएल (मुख्यालय) के लिए, उन सहायक कंपनियों का समेकित कोयला उत्पादन, जिन्होंने तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध घाटा नहीं उठाया है, बाद वाले श्रेणी के लिए माना जाता है। सीएसआर के तहत जो गतिविधियां की जा सकती हैं, वे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की धारा 135 के अनुसार हैं। सीएसआर फंड का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों में खर्च किया गया है:

क. स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता
ख. शिक्षा और आजीविका
ग. ग्रामीण विकास
घ. पर्यावरणीय स्थिरता
ङ. खेलों को बढ़ावा
च. आपदा प्रबंधन और राहत

सरकार की प्राथमिकता और अन्य विषयों में पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क. <u>स्वास्थ्य देखभाल:</u>

i. अस्पताल:

- एमसीएल द्वारा 493 करोड़ रू. की लागत से तालचेर, अंगुल जिला, ओडिशा में 500 बिस्तरों वाले अस्पतालों के साथ 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण।
- छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस), बिलासपुर में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन
- इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, कोलकाता (आईएन-के) में न्यूरोलॉजी उपचार संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए सहायता

ii. कोविड :

- कोविड-19 राहत पर कुल 269 करोड़ रुपये का खर्च (वित्त वर्ष 2011 के कुल खर्च का (48%)।
- भुवनेश्वर में 1300+ बिस्तरों वाला COVID अस्पताल
- तालचेर , ओडिशा में 150 बिस्तरों वाला समर्पित अस्पताल
- बिलासपुर और अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों वाले समर्पित अस्पताल
- कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान (केआईएमएस), हुबली में 100 बिस्तरों वाला आईसीयू
- पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ और मेघालय में सरकार को वैक्सीन परिवहन के लिए कोल्ड चेन उपकरण।
- मिशन प्रणवायु के तहत कुल 31 ऑक्सीजन संयंत्र (जिनमें से 25 सरकारी अस्पतालों में सीएसआर के तहत) स्थापित किए जा रहे हैं ।

ख. शिक्षा और कौशल विकास

- आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले झारखंड के मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान करने के लिए सीसीएल केलाल और सीसीएल की लाडली कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2013 से चल रहा है। आईआईटी, एनआईटी आदि जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब तक 300 से अधिक छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया है।
- 25 करोड़ रुपये की लागत से धारवाड़ और बागलकोट , कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूलों का पुनर्निर्माण ।
- सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी (सीपेट) के माध्यम से प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेडों मे सीआईएल की सहायक कंपनियों के कमान क्षेत्रों से 5,000 बेरोजगार युवाओं (8 वीं - 10 वीं पास) का प्रशिक्षण। 2,000 युवाओं का पहला चरण पूरा हो चुका है और प्रशिक्षुओं ने लगभग 10,000 रु प्रति माह के शुरुआती वेतन के साथ नौकरी हासिल की है। । प्लेसमेंट प्रतिशत 84 फीसदी रहा है।
- लघु धारक कुक्कुट परियोजना में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदिवासी महिलाओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण । यह परियोजना 500 से अधिक परिवारों को 3000 - 3500 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में मदद कर रही है।

ग. जल, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण

- 55 करोड़ रुपये की लागत से अंगुल जिले, ओडिशा के तलचर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए पाइप जलापूर्ति योजनाएं ।
- विभिन्न रेलवे जोन के 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्रति ब्लॉक 25 लाख रुपये की लागत से बेहतर स्वच्छता के लिए पूर्वनिर्मित शौचालय ब्लॉकों की स्थापना।
- हरियार छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत 15.56 करोड़ रुपये की लागत से ब्लॉक और सड़क किनारे वृक्षारोपण।

घ. ग्रामीण विकास

- 19 करोड़ रुपये की लागत से सीमावर्ती गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चमोली जिले, उत्तराखंड में सीमा सड़क निर्माण और संरेखण कार्य ।
- सिंगरौली, मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए17.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- सीसीडीपी- ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान और कृषि -बागवानी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए ओडिशा में एमसीएल के कमांड जिलों में 20 करोड़ रुपये की लागत से उत्थान परियोजना

ङ. खेल को बढ़ावा

- भोपाल, ग्वालियर और बैंगलोर में खेल के बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग के लिए 3 छात्रावासों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि को 75 करोड़ रुपये का योगदान।
- 25 करोड़ रुपये की लागत से बुर्ला , संबलपुर, ओडिशा में खेल परिसर का निर्माण।
- झारखंड की नवोदित खेल प्रतिभाओं को राष्ट्र के लिए संभावित पदक विजेता बनाने के लिए पहचान और आवासीय प्रशिक्षण के लिए होटवार , रांची में खेल अकादमी चलाना

च. <u>आपदा प्रबंधन</u>

- 2019 में चक्रवात फानी के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत पारेषण लाइनों के पुनर्निर्माण के लिए ओडिशा विद्युत ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- 15.60 करोड़ रुपये की लागत से भारत के एकमात्र नदी द्वीप जिला माजुली , असम में बाढ़ प्रभावित लोगों का पुनर्वास और आजीविका विकास ।
- महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों/राज्य सरकार को 90 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता ।
- पीएम–केयर्स फंड में 222.25 करोड़ रुपये का योगदान (जिसमें से 101.25 करोड़ रुपये सीएसआर से)

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सीएसआर सांविधिक आवश्यकता (रु. करोड़)	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)
2018-19	353.98	416.47
2019-20	396.20	587.84
2020-21	434.51	553.85
2021-22 (अप्रैल - मार्च)	450.63	507.18*

*आंकड़े अनंतिम हैं और लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

पिछले तीन वर्षों (2018-19-2020-21) के दौरान कार्यकलापवार व्यय:

सहायक	स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता (रु. करोड़)	शिक्षा और आजीविका (रु. करोड़)	ग्रामीण विकास (रु. करोड़)	पर्यावरणीय स्थिरता (रु. करोड़)	खेल को बढ़ावा	आपदा प्रबंधन और राहत (रु. करोड़)	अन्य (रु. करोड़)	कुल (रु. करोड़)
ईसीएल	10.16	15.90	9.24	3.58	0.17	0.09	0.36	39.50
बीसीसीएल	7.02	4.64	1.58	0.27	0.00	0.00	0.05	13.56
सीसीएल	83.61	9.41	4.97	3.08	27.84	0.00	21.72	150.63
डब्ल्यूसीएल	8.87	5.15	4.00	0.90	0.44	0.10	0.33	19.79
एसईसीएल	156.92	13.34	11.12	17.99	0.09	0.00	7.07	206.53
एनसीएल	62.18	116.05	73.72	10.58	3.43	20.00	0.87	286.83
एमसीएल	270.03	160.14	60.55	17.63	16.64	3.29	9.72	538.00
सीएमपीडीआई	4.46	3.86	0.38	0.21	0.00	0.00	0.40	9.31
कोल इंडिया	181.34	31.52	27.07	1.10	0.36	50.80	1.82	294.01
कुल	**784.59**	**360.01**	**192.63**	**55.34**	**48.97**	**74.28**	**42.34**	**1558.16**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए थीम-वार आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 21-22 में शुरू की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं:

सीआईएल और सहायक कंपनियां 30 अस्पतालों में 35,547 एलपीएम की कुल क्षमता के साथ 31 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रही हैं । ये संयंत्र 5,159 बिस्तरों को ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं। परियोजना की कुल लागत 46.24 करोड़ रुपये है।

1. ईसीएल द्वारा झारखण्ड में दुमका जिले के नवनिर्मित अस्पताल भवन में 3.45 करोड़ रुपये की लागत से 200 बिस्तरों वाले समर्पित कोविड अस्पताल (डीसीएच) की स्थापना ।
2. एमसीएल द्वारा कला, संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए माहिंगुला मंदिर, तालचेर के पास नाट्य मंडप और अन्य संरचनाओं के लिए 9.32 करोड़ रुपये की लागत से धन उपलब्ध कराना ।
3. एनसीएल द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को कोविड रोगियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने हेतु 10 करोड़ रुपये की सहायता।
4. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के स्याहिमुडी में कोविड केयर सेंटर को सुसज्जित करने के लिए एसईसीएल द्वारा रु. 5 करोड़ की सहायता।
5. सीसीएल द्वारा झारखण्ड के चतरा जिले के 30 स्कूलों में 1.03 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल कक्षाओं की स्थापना ।
6. कोविड-19 राहत के लिए बीसीसीएल द्वारा जिला प्रशासन, धनबाद को 1.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
7. सीआईएल द्वारा सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता में कैंसर के इलाज के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर रेडियोथेरेपी यूनिट की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
8. सीआईएल द्वारा सिलचर , असम में सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के लिए 5.04 करोड़ रु. की लागत से 40 बिस्तरों वाले आईसीयू सुविधा की स्थापना
9. 26 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नागपुर के अस्पताल भवन की एक मंजिल के विकास में वित्तीय सहायता। ।
10. जिला अस्पताल, सिमडेगा में 1 करोड़ रु. की लागत से सीटी स्कैन मशीन की स्थापना एवं केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना।
11. 2 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के संचालन के क्षेत्रों में पायलट पैमाने पर नवीन ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का प्रसार।

IMPLEMENTATION
OBJECTIVE
STRATEGY
ACT
ACTION PLAN
CHECK
COLLABORATION
SCHEDULE

अनुलग्नक -I

कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप पर दस्तावेज़ कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं-

mission-gasification-coal-statistics/national-coal.gov.in/en/major//:https

अनुलग्क-II

सीआईएल में एमडीओ परियोजनाओं की स्थिति-30-03-22

15 एमडीओ परियोजनाओं का सार		
वे परियोजनाएं जिनमें उत्पादन प्रारंभ हुआ	शून्य	
वे परियोजनाएं जिनमे कार्य सौंपा गया	5	सियारमल ओसी, केबीपी ओसी, चन्द्रगुप्त ओसी, केतकी यूजी, सुभद्र ओसी
खोली गई बोली	3	मदन नगर ओसी, पेलमा ओसी, पीपरवार यूजी
जिनकी निविदा पुन: दी जानी है	2	दुर्गापुर ओसी और संघ मित्रा ओसी
जारी की गई एनआईटी	3	पत्रातु यूजी, इटापारा ओसी और कपूरिया यूजी
जो एनआईटी जारी की जानी है	2	बालभद्र ओसी, परेज ईस्ट यूजी
कुल परियोजनाएं	15	

सीआईएल में एमडीओ परियोजनाओं की स्थिति-30-03-22					
क्र.सं.	**एमडीओ परियोजनाएं**	**संख्या**	**सीएपी**	**परियोजना का नाम**	**टिप्पणी**
1	एमडीओ परियोजनाएं	15	170.58	10 ओसी और 5 यूजी	
चालू की गई परियोजनाएं:					
1.1	उत्पादन प्रारंभ	0	0	-	-
जारी एलओए/कार्य आदेश					
1.2	सौंपा गया कार्य	5	95.87	1. सियारमल ओसी (50 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ-मई 22)	मैसर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड को दिनांक 04.03.2021 को एलओए जारी किया गया। संविदा करार दिनांक 01.06.21 को हस्ताक्षरित किया गया।
				2.केबीपी ओसी (5 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ-मार्च-24)	मैसर्स पीएमपीएल-एएमआर कंर्सोटियम को दिनांक 22.01.21 को एलओए जारी किया गया। संविदा करार दिनांक 26.06.21 को हस्ताक्षरित किया गया।
				3. चन्द्रगुप्त ओसी (15 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ्र-मार्च-24)	मैसर्स एसआईएमएल-एमआरकेआर कंसोर्टियम को दिनांक 20.12.21 को एलओए जारी किया गया। 18.03.2022 को करार पर हस्ताक्षर किया गया
				4.केतकी यूजी (0.87 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ-फरवरी 24)	मैसर्स एसएमएस लिमिटेड को दिनांक 10.03.2022 को एलओए जारी किया गया।
				5.सुभद्रा ओसीपी (25 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ- दिसंबर 24)	मैसर्स एसएल माइनिंग को दिनांक 22.03.2022 को एलओए जारी किया गया।
खोली गई बोली					
				1. मदन नगर ओसी (12 एमटीवाई (उत्पादन का प्रारंभ- जुलाई 24)	मैसर्स ईएमआईएल 1180.00 रू./ टीई के उद्धृत के साथ एल-1 बोली दाता के रूप में आया। एल-1 बोलीदाता द्वारा दिनांक 13.01.22 को मूल्य औचित्य प्रस्तुत किया गया किन्तु उन्होंने दर कम नही किया है। विक्रय मूल्य के विभिन्न संयोजन (विद्युत क्षेत्र, गैर-विद्युत क्षेत्र और ई-नीलामी के विभिन्न संयोजन के अंतर्गत व्यवहार्यता निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 03.03.22 को सीएमपीडीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया। टीसी बैठक दिनांक 04.03.22 और 14.03.22 को संपन्न हुई। टीसी ने कार्य सौंपने की सिफारिश की और इसे एसईसीएल के सीओएफडी द्वारा अनुशांसित किया गया है। एसईसीएल बोर्ड में दिनांक 29.03.2022 को कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया है।

1.3	खोली गई बोली	3	27.87	2. पैलमा ओसीपी (15 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ-जुलाई 24)	मैसर्स एईएल 849 रू. के उद्धृत दर के साथ एल-1 बोलीदाता के रूप में आया। एल-1 बोलीदाता द्वारा दिनांक 28.01.2022 को मूल्य का औचित्य प्रस्तुत किया गया, लेकिन अपने प्रस्ताव में दर में कमी नहीं की है। विक्रय मूल्य के विभिन्न संयोजन (विद्युत क्षेत्र, गैर-विद्युत क्षेत्र और ई-नीलामी) के अंतर्गत व्यवहार्यता निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 03.03.22 को सीएमपीडीआई द्वारा प्रस्तुत की गई। टीसी बैठक 04.03.22 और 14.03.22 को संपन्न हुई। टीसी ने कार्य प्रदान करने की सिफारिश की और इसकी अनुशंसा एसईसीएल के सीओएफडीओ द्वारा की गई है।
				3. पीपरवार यूजी (0.87 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ-अगस्त, 237)	बोली 24.01.22 को खोली गई। तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया। बोली तकनीकी मूल्याकंन के अंतर्गत हुई। बोलीदातओं को दिनांक 26.02.22 तक पुष्टिकारी प्रश्नो के उत्तर देने का अनुरोध किया गया और सभी बोलीदाताओं ने 26.02.22 तक अपने उत्तर प्रस्तुत कर दिए है। दूसरे पुष्टिकारी प्रश्नों का उत्तर भी दिनांक 21.03.22 को बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन चल रहा है। दिनांक 14.04.22 को कार्य सौंप दिया जाएगा।
वे परियोजनाएं जिनकी निविदा फिर से दी जानी है					
1.4	जिनकी निविदा फिर से दी जानी है	2	26.00	1. संघमित्रा ओसी (20 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ- अप्रैल, 24)	दिनांक 16.03.22 को निविदा रद्द कर दी गई। प्रस्ताव अद्यतन खनन प्रभार सीएमपीडीआई, आरआई-III द्वारा तैयार किया जा रहा है। आगे फिर से निविदा देने हेतु सीसीएल में इस पर विचार किया जा रहा है।
				2. दुर्गापुर ओसीपी (6 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ- जून 24)	बोली 15.12.21 को खोली गई। कोई बोली प्राप्त नही हुई। 17.12.21 को फिर निविदा दी गई। बोली 24.01.22 को खोली गई। कोई बोली प्राप्त नही हुई । दिनांक 02.02.22 को फिर से निविदा दी गई। बोली 14.03.22 को खोली गई किन्तु कोई बोली प्राप्त नही हुई। पुन: निविदा देने के लिए एसईसीएल में विचाराधीन है।

एनआईटी जारी किया गया					
1.5	एनआईटी जारी किया गया	3	10.33	1. पत्रातु एबीसी यूजी (5 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ- सितंबर, 24)	एनआईटी दिनांक 21.01.22 को जारी किया गया। बोली दिनांक 19.04.22 को खोली गई
				2. इटापारा ओसी (3.5 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ-मार्च, 24)	विशिष्ट रूप से निर्मित एनआईटी दस्तावेज दिनांक 03.03.22 को ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 25.03.22 को एनआईटी जारी किया गया।
				3. कपूरिया यूजी (1.83 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ्र- दिसंबर, 25)	बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित विशिष्ट रूप से निर्मित एनआईटी दस्तावेज दिनांक 30.03.22 को जारी किया गया।
जारी किया जाने वाला एनआईटी					
1.6	जारी किया जाने वाला एनआईटी	2	10.51	1.बालभद्र ओसी (10 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ- जून, 25)	सीआईएल बोर्ड ने दिनांक 24.01.22 को बालभद्र ओसीपी के पीआर को अनुमोदित किया है। संक्षिप्त पीआर और एनआईटी दस्तावेज को आरआई-7 में अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिनांक 15.04.22 को एनआईटी जारी।
				2. परेज ईस्ट यूजी (0.51 एमटीवाई) (उत्पादन का प्रारंभ- नवंबर,24)	पीआर और एनआईटी को दिनांक 07.03.22 को सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। एनआईटी 30.03.2022 को जारी किया जाएगा।
	कुल एमडीओ परियोजना	**15**	**170.58**		